

(c) if so, the particular reasons therefor and whether the approval of Registrar of Cooperative Societies has since been sought for such an amendment in bye-laws?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Board was advised that no amendment of the bye-laws was involved and so the question of referring this particular issue to the Registrar Cooperative Societies did not arise. The decision has been given on the practical consideration of keeping the number of delegates within reasonable limits.

Raman Hydel Project

71. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Raman Hydel Project has been cleared by the Planning Commission;

(b) if so, what is the total amount involved; and

(c) how long it will take to complete the project?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) No, Sir. Approval for sanctioning the Raman Hydro-electric project is under consideration of the Government.

(b) and (c). Does not arise at this stage.

कच्छ में आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

72. श्री अनन्त बबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा समुदाय के उन लोगों का जो भारत-पाक युद्ध के बाद कच्छ में

आ गये थे, भारतीय नागरिकता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में सरकार से अनेक बार अनुरोध किया था ; और यदि हां, तो उन अनुरोधों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख). सोडा समुदाय के व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। सभी पहलुओं पर विचार करने पर उनको यह सुविधा प्रदान करना उपयुक्त नहीं समझा गया। आशा की जाती है कि पाकिस्तान सरकार आवश्यक परिस्थितिय बना कर उपयुक्त उपाय करेगी ताकि प्रभावित व्यक्ति सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने घरों को लौट सकें।

बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजा जाना

73. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में काफी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और उसकी उपयोगिता क्या थी ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) और (ख). लोक सभा के हाल के चुनाव कराने की घोषणा से पहले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 4 बटैलियन बिहार सरकार को उनके अनुरोध पर विधि और व्यवस्था बनाये रखने में उनकी मदद करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। चुनाव के दौरान

विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त 2½ बटालियन उपलब्ध की गई थी। इन अतिरिक्त बटालियनों को वापिस बुला लिया गया है और इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की चार बटालियन राज्य सरकार के पास है।

बिहार के विकास के लिये पांचवीं योजना में नियतन

74. श्री युवराज : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के योजनाबद्ध विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि का नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस राज्य की जनसंख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस राज्य को कब तक सहायता देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के लिए 24 और 25 सितम्बर, 1976 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सभी राज्यों की योजना के आकार को अन्तिम रूप दिया गया था। पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के लिए बिहार राज्य का परिव्यय 1,296.06 करोड़ रुपये है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए फार्मुले के आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय न केवल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार प्रकट किए गए पिछड़ेपन का ही ध्यान रखा जाता है, बल्कि सम्बन्धित राज्यों द्वारा संसाधन जुटाने के लिए किए

गये प्रयासों और उनकी विशेष समस्याओं का भी ध्यान रखा जाता है।

आपात स्थिति के दौरान मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये कार्यकर्ता

75. श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25-26 जून, 1975 को आपात स्थिति लागू होने पर केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसके अधिकारियों को किन श्रेणियों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के आदेश भेजे गये थे; और

(ख) क्या गिरफ्तारी सम्बन्धी उक्त आदेश अथवा अन्य आदेश अभी भी उपलब्ध हैं ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) :

(क) जून, 1975 में आपात स्थिति की उद्घोषणा के समय, गिरफ्तार किए जाने वाले सरकारी अधिकारियों की श्रेणियों का ठीक ठीक उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कोई आदेश जारी नहीं किए गये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Inquiry into atrocities on Political Prisoners in Jails during Emergency

76. SHRI HARIVISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to institute a public independent inquiry into the atrocities perpetrated on political prisoners in various jails during the period of Emergency, from June 26, 1975 to date; and

(b) if so, when, and its terms of reference ?